भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 841

जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2023 को दिया जाना है

न्यायसंगत संक्रमण नीति

841. श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास खानों और अन्य जीवाश्म ईंधन आधारित क्षेत्रों के बंद होने के कारण खत्म हुई नौकरियों का कोई अनुमान है, यदि हाँ, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) सरकार द्वारा विश्व बैंक के साथ स्थापित ''न्यायसंगत संक्रमण परियोजना'' (जस्ट ट्रांजिशन पॉलिसी) के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के कारण बंद होने वाली नौकरियों से प्रभावित कामगारों की सुरक्षा और सहायता के लिए पेरिस समझौते के अनुरूप ''न्यायसंगत संक्रमण नीति'' अपनाने का विचार रखती है; और

(घ) यदि नहीं, तो हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के कारण खत्म हुई नौकरियों से प्रभावित कामगारों के बचाव और सहायता के लिए सरकार की क्या योजना है?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) : वर्तमान परिपाटी के अनुसार, आगामी तीन से चार वर्षों में बंद होने वाली सरकारी कोयला कंपनियों की खानों में तैनात जनशक्ति को कोयला कंपनियों की निकटवर्ती खानों में पुनः तैनात किया जाएगा। इस प्रकार, जो खानें निकट भविष्य में बंद होने के कगार पर हैं, वे एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न कोलफील्ड्स में फैली हुई हैं और कोयला खानों के बंद होने के

कारण सरकारी कोयला कंपनियों में किसी कर्मचारी की छंटनी नहीं की गई है। साथ ही, राष्ट्र की बढ़ती आवश्यकता के अनुसार कोयला उत्पादन को बनाए रखने के लिए नई खानें खोली जा रही हैं।

(ख) : सरकार ने अभी तक विश्व बैंक के साथ कोई ''न्यायोचित बदलाव परियोजना'' स्थापित नहीं की है। फिर भी, विश्व बैंक वर्तमान में "भारत के कोयला खान बंद करने की रुपरेखा का समर्थन, सभी के लिए एक न्यायोचित बदलाव प्राप्त करना" नामक एक तकनीकी सहायता परियोजना को लागू कर रहा है। यह तकनीकी सहायता संसाधन समापन और क्षेत्र के भू-स्थानिक मानचित्रण के कारण पहले से ही बंद, परित्यक्त और बंद होने वाली खानों के अध्ययन के लिए अभिप्रेत है।

(ग) और (घ) : यद्यपि, यथासमय कुछ खानें भंडारों की समाप्ति के कारण बंद हो सकती हैं, लेकिन साथ ही, ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई नई कोयला खानों को प्रचालित किया जा रहा है। ये खानें न केवल राष्ट्र की वहनीयता और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर रही हैं, बल्कि बेहतर आजीविका सुनिश्चित करने और कोयला क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बंद होने वाली खानों से नई खानों में कामगारों के पुनः नियोजन और नए रोजगार के लिए नए अतिरिक्त अवसर भी प्रदान कर रही हैं।

इसलिए, भारत में, निकट भविष्य में कोयले से बदलाव या न्यायोचित बदलाव नहीं हो रहा है। यद्यपि भारत नवीकरणीय/गैर-जीवाश्म आधारित ऊर्जा पर जोर दे रहा है, लेकिन संधारणीय विकास और गरीबी उन्मूलन को सक्षम करने के लिए सस्ती ऊर्जा उपलब्धता, पहुंच और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा बास्केट में कोयले की हिस्सेदारी आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण रहने वाली है।

****